



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन 1940 (श0)

(सं0 पटना 270) पटना, सोमवार, 25 फरवरी 2019

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

14 फरवरी 2019

सं० 7प/वि-03-03/2018/1186 पं०रा०—सं० स्था० नि० को० (01)-08/2015-07— भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार पंचायती राज अंकेक्षण संवर्ग के सृजन की घोषणा करते हुए, बिहार पंचायती राज अंकेक्षणों की भर्ती की प्रक्रिया और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।— (1) यह नियमावली “बिहार पंचायती राज अंकेक्षण संवर्ग नियमावली, 2019” कहलाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जहां बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) या कैंन्टोनमेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम II, 1924) के उपबंध लागू हैं।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ ।— जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

- (i) “सरकार” से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (ii) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;
- (iii) “विभाग” से अभिप्रेत है पंचायती राज विभाग, बिहार;
- (iv) “पंचायती राज संस्था” से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्र के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ख के अधीन गठित, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्;
- (v) “सेवा” से अभिप्रेत है बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा;
- (vi) “सदस्य” या “सेवा के सदस्य” से अभिप्रेत है बिहार पंचायत अंकेक्षण संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति;
- (vii) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची;
- (viii) “आयोग” से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
- (ix) “संवर्ग नियंत्रि प्राधिकार” से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग

3. **संवर्ग की संरचना** 1— (1) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

(2) इस संवर्ग में निम्नलिखित कोटि के पद होंगे —

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	पदों की स्थिति	नियुक्ति प्राधिकार
1	अंकेक्षक (पंचायती राज)	मूल कोटि	अराजपत्रित	प्रधान सचिव/ सचिव
2	वरीय अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज)	प्रथम प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित	प्रधान सचिव/ सचिव
3	जिला अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज)	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित	सरकार
4	मुख्य अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज)	तृतीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित	सरकार

(3) यह संवर्ग अंकेक्षण निदेशालय के रूप में पंचायती राज विभाग के अधीन गठित होगा तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के आंतरिक अंकेक्षण के लिए प्रवृत्त होगा। अंकेक्षण निदेशालय निदेशक, पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। निदेशालय का मुख्यालय पटना होगा।

(4) प्राधिकृत बल 1— राज्य सरकार, समय-समय पर, इस सेवा के पदबल का अवधारण करेगी और इस सेवा में इस नियमावली के आरम्भ की तिथि को स्वीकृत बल के अतिरिक्त स्थायी/अस्थायी पदों का सृजन कर सकेगी।

4. **रिक्तियों में आरक्षण** 1— भर्ती और प्रोन्नति प्रक्रिया में राज्य सरकार द्वारा अवधारित आरक्षण के नियमों/रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।

5. **रिक्तियों का अवधारण और आयोग को संसूचन** 1— सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या का अवधारण हरेक वर्ष 1ली अप्रैल को किया जायेगा और इस प्रकार अवधारित रिक्तियों की अधियाचना आयोग/सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट एजेन्सी को 30 अप्रैल तक भेज दी जायेगी।

6. **आयोग द्वारा सीधी भर्ती** 1— अंकेक्षक (पंचायती राज) के 100 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएँगे। विज्ञापन प्रकाशित कर तथा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इस सेवा की मूल कोटि के पद अर्थात् "अंकेक्षक" के लिए नियुक्ति की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जायेगी।

7. **पात्रता** 1— (1) नियम-6 में उल्लिखित पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होगी। इसके अतिरिक्त एम0बी0ए0 (वित्त), सी0ए0, आई0सी0डब्लू0ए0 और सी0एस0 डिग्रीधारी इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(2) मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा विज्ञापन वर्ष की 1ली अगस्त को 21 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय-समय पर, अवधारित की जाएगी।

8. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा** 1— आयोग नियम 9 के अनुसार मेधा सूची तैयार करेगा। आयोग अधियाचना के अनुरूप सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा राज्य सरकार (पंचायती राज विभाग) को भेजेगी। यदि कोई अभ्यर्थी सेवा में योगदान नहीं करता हो तो ऐसी रिक्तियाँ अग्रणीत की जायेंगी।

9. **आयोग द्वारा सरकार को अनुशंसा एवं नियुक्ति प्राधिकार** 1— आयोग सफल अभ्यर्थियों की सूची मेधा-क्रम में तैयार करेगा। जहाँ दो या अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एक ही हो, वहाँ उनका मेधा-क्रम का अवधारण उनकी शैक्षणिक योग्यता और/या उम्र के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार तैयार की गई मेधा सूची नियुक्ति की अनुशंसा के साथ पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। आयोग की अनुशंसा विभाग में इसकी प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष तक विधिमान्य रहेगी। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोग सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित न्यूनतम अर्हतांक संबंधी प्रावधान का अनुपालन करेगा।

10. **वरीयता** 1—(1) इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त सदस्यों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा-क्रम के अनुसार होगी।

(2) किसी वर्ष में संवर्ग में प्रोन्नत सदस्यों की आपसी वरीयता उनके प्रोन्नति आदेश से अवधारित होगी।

(3) विभाग संवर्ग के सभी पदों की वरीयता सूची संधारित करेगा।

(4) इस सेवा के सदस्यों की पारस्परिक वरीयता का अवधारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिश्चित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगी।

11. **परिवीक्षा अवधि** 1— (1) सेवा के नवनियुक्त सदस्य पदग्रहण की तारीख से दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

- (2) परीवीक्षा अवधि में कर्मचारी की सेवा और आचरण यदि संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, परीवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। यदि बढ़ाई गई अवधि में भी सेवा संतोषप्रद न पायी जाती है तो ऐसे कर्मचारी को सेवा से हटाया जा सकेगा।
- (3) परीवीक्षाधीन (व्यक्ति) को परीवीक्षा अवधि में यथाविहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होना होगा। विभागीय परीक्षा का आयोजन तथा एतदर्थ विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा किया जाएगा। प्रथम वेतन वृद्धि के उपरान्त अगली वार्षिक वेतनवृद्धि हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा/कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही अनुमान्य होगी।
- 12. संपुष्टि।—** (1) परीवीक्षा पर नियुक्त अंकेक्षक को, परीवीक्षा अवधि पूरा होने पर, संपुष्टि किया जा सकेगा बशर्ते वह विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए तथा वह प्राक् संपुष्टि प्रशिक्षण पूरा कर ले।
- (2) **अंकेक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा:—** परीवीक्षा पर नियुक्त अंकेक्षक को संपुष्टि और वरीय अंकेक्षण अधिकारी के उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। एक वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अंकेक्षक इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।
- 13. प्रोन्नति द्वारा भर्ती।—** (1) मूल कोटि के अंकेक्षक पद से भिन्न सभी पद प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जाएगी। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिर्धारित कालावधि संबंधी प्रावधान का अनुपालन आवश्यक होगा।
- (2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।
- (3) प्रोन्नति के लिए सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की भी उपयुक्तता अभिनिश्चित की जाएगी अर्थात् सभी अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्तता का मानदंड एक होगा। विहित न्यूनतम मानदंड पूरा करनेवाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण की सीमा तक किया जाएगा।
- 14. वेतनमान।—** सेवा की विभिन्न कोटियों के पदों का वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित किया जाय।
- 15. कार्यक्षेत्र से संबंधित अनुबंध।—** (1) इस सेवा के सदस्य को अंकेक्षण कार्य के लिए बिहार राज्य के भीतर या बाहर किसी भी पंचायती राज संस्था और ग्राम कचहरी में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।
- (2) इस सेवा के किसी सदस्य को उसकी प्रारिथिति से तुलनीय किसी बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
- 16. प्रशिक्षण।—** (1) इस सेवा के सदस्य को राज्य सरकार द्वारा विहित अवधि के लिए राज्य के भीतर या बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सकेगा। प्रशिक्षण की समाप्ति पर किए गए मूल्यांकन को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ध्यान में रखा जा सकेगा।
- (2) संपुष्टि पूर्व प्रशिक्षण के दो पहलू होंगे— सैद्धान्तिक प्रशिक्षण और प्रयोगात्मक प्रशिक्षण। सैद्धान्तिक प्रशिक्षण और प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की अवधि क्रमशः तीन माह और छह माह की होगी।
- 17. अवशिष्ट मामले।—** इस संवर्ग के लिए अन्य सेवाशर्तें, यथा—अनुशासनिक कार्यवाई, छुट्टी, अनुमान्य सेवानिवृत्ति लाभ आदि, जिनके लिए इस नियमावली में प्रावधान नहीं किए गए हैं के संदर्भ में राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए अवधारित सुसंगत उपबंध लागू होंगे।
- 18. विनियमावली।—** इस नियमावली के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए पंचायती राज विभाग ऐसी विनियमावली बना सकेगा जो इस नियमावली के किसी उपबंध के असंगत न हो।
- 19. निर्वचन।—** इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में शंका उत्पन्न होने पर विषय विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।
- 20. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।—** यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् ऐसे आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो।
- 21. निरसन एवं व्यावृत्ति।—** (1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा, समय-समय पर, पूर्व से निर्गत संकल्प/नियमावली/ आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्यवाई की गई थी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 14th February 2019

No. 7Pa/Vi-03-03/2018/1186/P.R.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby, declaring the creation of "Bihar Panchayati Raj Audit Cadre" makes the following Rules to regulate the procedure of recruitment and service conditions of the Panchayati Raj Auditors:—

1. Short title and commencement .—

- (1) These rules may be called the Bihar Panchayati Raj Audit Cadre Rules, 2019.
- (2) It shall extend to the whole State of Bihar except the areas to which the provisions of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11 of 2007) or Cantonment Act, 1924 (Act II, 1924) apply.
- (3) It shall come into force at once.

2. Definitions .- Unless and otherwise required in the context, in these Rules –

- (i) **"Government"** means the Government of Bihar;
- (ii) **"Governor"** means the Governor of Bihar;
- (iii) **"Department"** means the Panchayati Raj Department, Bihar;
- (iv) **"Panchayati Raj Institutions"** means Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad, as the case may be, constituted under Article 243-B of the Constitution of India for the rural areas;
- (v) **"Service"** means Bihar Panchayat Audit Service;
- (vi) **"Member or Member of the Service"** means the person appointed in the Bihar Panchayati Raj Audit service;
- (vii) **"Schedule"** means the schedule attached to these Rules;
- (viii) **"Commission"** means the Bihar Public Service Commission;
- (ix) **"Cadre Controlling Authority"** means Principal Secretary/Secretary Panchayati Raj Department;

3. Composition of the cadre .- (1) This cadre will be a state level cadre.

- (2) This cadre will consist of the following categories of posts :—

Sl. No	Post	Category	Status of the Post	Appointing Authority
1	Auditor (Panchayati Raj)	Basic Category	Non Gazetted	Principal Secretary/ Secretary
2	Senior Audit Officer (Panchayati Raj)	1st Stage of promotion	Non Gazetted	Principal Secretary/ Secretary
3	District Audit Officer (Panchayati Raj)	2nd Stage of promotion	Gazetted	Government
4	Chief Audit Officer (Panchayati Raj)	3rd Stage of promotion	Gazetted	Government

- (3) This cadre will be constituted as an Audit Directorate under the Panchayati Raj Department and will come into force for internal audit of Panchayati Raj Institutions. The Audit Directorate will function under the administrative control of the Director, Panchayati Raj Department. Headquarters of the Directorate will be at Patna.
- (4) Authorized Strength - The State Government shall determine the post strength of this service, from time to time and may create permanent/temporary posts of this service in addition to the sanctioned strength on the date of commencement of the Rules.

4. Reservation in vacancies .- The Rules/Rosters of Reservation determined by the State Government will be followed in recruitment and promotions.

5. Determination of vacancies and intimation to the Commission .- The number of vacancies to be filled by direct recruitment or by promotion shall be determined on 1st April of every year and the requisition of vacancies so determined will be sent to the Commission or the Agency nominated for this purpose by the Government upto 30 April.

6. Direct Recruitment by the Commission .- 100% posts of Auditor (Panchayati Raj) shall be filled by direct recruitment. By publishing an advertisement and on the basis of competitive examination, recommendation for appointment to the posts of the basic category of this service i.e. "Auditor (Panchayati Raj)" shall be made by the Bihar Public Service Commission.

7. Eligibility .—(1) The minimum educational qualification for the post mentioned in Rule 6 shall be Bachelor degree from recognized University in any one of the subjects Commerce, Economics, Mathematics and Statistics. In addition to this, candidates having MBA (Finance), C.A, ICWA and C.S degree will also be eligible to apply for this post.

(2) The minimum age limit for direct recruitment to the post of basic category shall be 21 years on 1st August of the year in which advertisement is published and the maximum age limit will be same as may be determined by the State Government (General Administration Department), from time to time.

8. Recommendation of the candidates by the Commission .—The Commission shall prepare a merit list as per Rule 9. The Commission shall recommend the successful candidates to the State Government (Panchayati Raj Department) in conformity with the requisition. In case any candidate does not join the service, such vacancies shall be carried forward.

9. Recommendation to the Government by the Commission and the Appointing Authority .— The Commission shall prepare the list of the successful candidates in order of merit. Where the marks obtained by two or more candidates are same, their order of merit shall be determined on the basis of educational qualification and /or age. The merit list so prepared along with the recommendation of appointment shall be made available by the Commission to the Panchayati Raj Department, Government of Bihar. The recommendation of the Commission shall be valid for a period upto one year from the date of its receipt in the Department. For selection of suitable candidates, the Commission will follow the provisions relating to the minimum qualifying marks determined by the General Administration Department.

10. Seniority .—(1) Inter-se-Seniority of the members appointed through direct recruitment under these Rules shall be according to the merit order recommended by the Commission.

(2) Inter-se-seniority of the members promoted in the cadre in a year shall be determined by their promotion orders.

(3) The Department shall maintain the seniority list of all the posts in the cadre.

(4) The Inter-se-seniority of the members of this service will be determined on the basis of principles and procedures determined by the General Administration Department, Bihar.

11. Probation Period .—(1) Newly recruited members of the service shall be on probation for two years from the date of joining.

(2) In case the service and conduct of the employee is not found satisfactory in the probation period, the probation period may be extended, with reasons to be

recorded in writing, for one year. If the service is not found satisfactory even in the extended period, such employee may be removed from service.

- (3) In the probation period, the probationer shall have to obtain training as may be prescribed and pass the Departmental Examination. The Central Examination Committee, Board of Revenue, Bihar shall held the Departmental Examination and determine the subject, syllabus and procedure for this purpose. Next annual increment after the first increment shall be admissible only after passing the Hindi Noting and Drafting Examination/ Computer Proficiency Test.

12. Confirmation .- (1) Auditors appointed on probation may be confirmed after completion of probation period provided that he/she passes the Departmental Examination and completes the pre-confirmation training.

- (2) **Departmental Examination for Auditors—** Auditors appointed on probation will have to pass the Departmental Examination for confirmation and promotion to the higher scale of Senior Audit Officer. Auditors completing one year of service will be eligible to sit in this examination.

13. Recruitment by Promotion .—(1) All posts other than the post of Auditor of basic category shall be filled by promotion. Promotions will be made on the recommendation of the Departmental Promotion Committee. It will be essential to comply with the provisions relating to kalawadhi, determined by the General Administration Department.

- (2) Department shall issue separate order regarding constitution of the departmental promotion Committee.
- (3) At the time of promotion, the suitability of the candidates of Scheduled Castes/Scheduled Tribes shall be ascertained along with the candidates of General Category, that is to say the criterion of suitability for all the candidates shall be the same. The candidates of Scheduled Castes/Scheduled Tribes fulfilling the prescribed minimum criterion may be selected to the limit of reservation.

14. Pay Scale .- The pay-scale of the posts of different categories of the service shall be the same as may be determined by the State Government, from time to time.

15. Stipulation regarding working area .- (1) The members of this service may be deputed for audit work in any Panchayati Raj Institution and Gram Katchahry within or outside the State of Bihar.

- (2) The State Government will have the right to post or depute any member of this service to any such ex-cadre post which is comparable to his/her status.

16. Training .- (1) The members of this service may be sent for training, within or outside the state for a period prescribed by the State Government. The evaluation made at the expiry of the training may be taken into consideration by the Departmental Promotion Committee.

- (2) Before the confirmation, there will be two aspects of the training – Theoretical Training and Practical Training. The period of theoretical training and practical training shall be of three months and six months respectively.

17. Residual Matters .— In the context of the other service conditions for this cadre, such as disciplinary action, leave, admissible retirement benefits etc. for which provisions are not made in these Rules the relevant provisions determined for the employees/ officers of appropriate level of the State Government shall apply.

18. Regulations .—The Panchayati Raj Department may make such regulations, which are not inconsistent with any provisions of these rules, for implementation of the provisions of these Rules.

19. Interpretation .—If any doubt arises in the interpretation of any provision of these Rules, the matter will be referred to the Department and the decision of the Department, after consultation with the Law Department, will be final in this regard.

20. Power to remove difficulties .—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Rules, the Government may after consultation of the Law Department, by such order, which is not inconsistent remove the difficulty.

21. Repeals and savings .- (1) Any Order/ Rules/Resolution, already issued, from time to time, by the Department in respect of this cadre, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeals, any work done or any action taken under the said order/Rules/Resolutions will be deemed to be done or taken under these Rules as if it were in force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
AMRIT LAL MEENA,
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 270-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>